अपार्थेड के साथ साझेदारी: भारत में पेगासस जासूसी

भारतीय नागरिकों के स्मार्टफोन पर इस्राइली एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग के बारे में बड़े पैमाने पर हो रहे खुलासे में कई पत्रकार, विपक्षी नेता, यहां तक कि एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट का नाम भी सामने आया है। पेगासस स्पाइवेयर और एनएसओ ग्रुप खुद इस्राएल के अपार्थेड और कब्ज़े के मैट्रिक्स का हिस्सा हैं और हमारी सरकार के दमनकारी प्रतिमानों और तरीकों का बस नवीनतम आयात है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेरिस स्थित गैर-लाभकारी संस्था, फॉरबिडन स्टोरीज़, वास्तविक और संभावित लक्ष्यों के रूप में चुने गए फोन नंबरों की लीक हुई एक सूची पाने में सक्षम थी, जिसे उन्होंने पेगासस प्रोजेक्ट को दिया- जो कि मीडिया घरानों का समूह है जो एनएसओ और उसके ग्राहकों की जांच में सम्मिलित है। भारत ऐसे 10 ग्राहकों में से एक है। एनएसओ ग्रुप इस्राइली राज्य के साथ मिलकर काम करता है, जो कंपनी के स्पाइवेयर की हर बिक्री को मंजूरी देता है, और कंपनी खुद अपने उत्पादों को केवल "सत्यापित सरकारों" को बेचने का दावा करती है।

इसके पहले भी 2019 के अंत में व्हाट्सएप द्वारा कार्यकर्ताओं और वकीलों के खिलाफ़ पेगासस के उपयोग के बारे में एक खुलासा सामने आया था, जिनमें से कई भीमा कोरेगांव मामले से जुड़े थे। यह दिन के उजाले जैसे स्पष्ट है कि सरकार दमन या जासूसी के द्वारा किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए तैयार है जो उसकी आलोचना करते हैं और सच्चाई को सामने ला रहे है।

इस्राएल और एनएसओ समूह के साथ अपने सहयोग के माध्यम से सरकार ऐसी तकनीकों का उपयोग करती है जो फ़िलिस्तीनी लोगो के खिलाफ़ प्रयोग किये जाते हुए विकसित की गयी हैं। इस प्रकार इन तकनीकों को प्रखर बनाया जाता है, और फिर दुनिया भर के ग्राहकों को बेचा जाता है जो दमन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब से लेकर मैक्सिको तक, हंगरी से लेकर भारत तक -- शासकों द्वारा विरोध की आवाज़ों को निशाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते पत्रकार जमाल खशोगी और सेसिलियो पिनेडा बिर्टो मारे भी जा चुके हैं।

इसलिए, हम भारत सरकार से इस मामले की जांच के निष्कर्षों को सामने रखने की मांग तो करते ही हैं, पर साथ में हमें एक व्यापक वैश्विक गठबंधन की दिशा में भी काम करना चाहिए जो इस तरह की जासूसी और सरकारों की साँठ - गाँठ को चुनौती दे जिसके चलते ऐसी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की तकनीकें उन तक पहुँचती हैं -- जैसा कि हम इस्राएल के साथ देखते हैं।

एनएसओ को उसकी तकनीक द्वारा लक्षित लोगों की मौत और दमन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन यह केवल इस मामले का सिरा भर है।

जासूसी की तकनीकें आयात एक सरकारी नीति का परिणाम हैं जो इस्राएल को एक मॉडल के रूप में देखता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो इस्राइली वापसी के कानून का प्रतिबिम्ब है, जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और वहां 'इस्राएल-शैली की बस्तियों' के लिए दरवाज़े खोलना इसकी शुरुआत रहे हैं। लोकतंत्र विरोधी जासूसी के घोटाले से पता चलता है कि सत्ता में बैठे लोगों की इच्छा का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ इस्राएल के तरीकों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। आंतरिक रूप से, लोकतंत्र और समानता के लिए हमारे संघर्ष फ़िलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के साथ-साथ दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं।

हम मांग करते हैं और इनके लिए निरंतर संघर्ष की ओर अग्रसर हैं कि:

- जनता के पैसे का इस्तेमाल कर एनएसओ और ऐसी अन्य कंपनियों से साइबर सर्वेलन्स टेक्नोलॉजी की खरीद ख़त्म हो
- भारतीय नागरिकों के ख़िलाफ़ जासूसी और दमन को समाप्त हो
- अपार्थेड इस्राएल के साथ सैन्य और सुरक्षा संबंध समाप्त हो